

औद्योगिक भूखंडों का बनेगा लैंड बैंक, खुलेंगी नई इकाइयां

ग्रेनो, यमुना और नोएडा में औद्योगिक इकाइयों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए होगा सर्वे

माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में खाली पड़ी जमीनों पर नए उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सहित सभी प्राधिकरणों में औद्योगिक इकाइयों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण कराएगी। प्राधिकरणों में औद्योगिक भूखंडों का लैंड बैंक तैयार किया जाएगा।

खाली जमीन चिह्नित कर देश-विदेश की नई औद्योगिक इकाइयों को आमंत्रित किया जाएगा। संचालित और गैर संचालित औद्योगिक इकाइयों का डाटाबेस तैयार करने के लिए रिवेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) निकाली गई है। दरअसल, इनवेस्ट यूपी की ओर से सर्वेक्षण कराने को कंपनी आमंत्रित करने के लिए अब आरएफपी जारी कर दी गई है। एजेंसी का चयन उनकी विशेषज्ञता के आधार पर किया जाएगा।

एक एजेंसी को दो से अधिक पैकेज आवंटित नहीं किए जाएंगे। सर्वेक्षण एजेंसी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के बाद औद्योगिक

प्रदेश की 42 हजार इकाइयों में से 15 हजार गौतमबुद्ध नगर में

प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण और गोरखपुर विकास प्राधिकरण है। प्रदेशभर के इन सातों प्राधिकरण क्षेत्रों में करीब 42 हजार औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं, इनमें से 15 हजार इकाइयां गौतमबुद्धनगर में हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि गौतमबुद्ध नगर जिले में पांच हजार औद्योगिक इकाइयां और बढ़ सकती हैं।

इकाइयों का रिकॉर्ड तैयार करेगी। डाटा संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया गया है। सर्वेक्षण एजेंसी क्षेत्र में दौरे के दौरान वास्तविक समय की जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए ऐप का उपयोग करेंगी, जिसे बाद में सत्यापित और विश्लेषण किया जाएगा।

एयरपोर्ट के निर्माण के बाद कई देशों की नजर

■ नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही अमेरिका, कोरिया, जापान सहित कई और देशों की नजर यमुना व ग्रेटर नोएडा क्षेत्र पर जमी है। यहां अमेरिका की एक कंपनी ने शैक्षणिक संस्थान के लिए 100 हेक्टेयर जमीन की मांग भी की है। उम्मीद जताई जा रही है कि एयरपोर्ट के संचालन के बाद फॉर्च्यून-500, सहित देश विदेश की कई कंपनियों के लिए यह क्षेत्र पहली पसंद बनेगा। ऐसे में भूखंड का सर्वे और खाली जमीनों का डाटा बेस तैयार होने से इस क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा।

यह प्रक्रिया चार माह में पूरा किया जाएगा।

सर्वेक्षण में औद्योगिक भूखंडों से उनके आकार, जमीन उपयोग के प्रकार, उद्योग श्रेणी, परिचालन स्थिति और अन्य विवरण जैसे कर्मचारियों की संख्या और निर्मित उत्पादों को निर्धारित करने के लिए डाटा एकत्र किया जाएगा।